

Date - 26-04-2020

CC-2 - समकालीन भारत एवं शिक्षा
Contemporary India and Education

Unit - IV - RMSA

RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN
(RMSA)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
(पढ़े-चलो, बढ़े-चलो)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक अभियान है। इसका गठन वर्ष 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया तथा वर्ष 2010 में इसे सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। केन्द्र सरकार का मानना था कि एक अभियान के रूप में अर्थात् एक क्रांति के रूप में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा को सुलभ एवं मजबूत बनाया जा सकता है।

इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य प्रत्येक घर से अर्थात् दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर 5 वर्ष में नामांकन दर माध्यमिक स्तर पर 90 प्रतिशत तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का है। तथा माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाते हुए महिला-पुरुष भेदभाव, सामाजिक-आर्थिक और निःशक्तता बाधाओं को मिटाते हुए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को व्यापक सुलभता के साथ गुणवत्ता में सुधार करना है।

RMSA के उद्देश्य

- 2017 तक शत-प्रतिशत नामांकन प्राप्त करना।
- 2020 तक शत-प्रतिशत लहराव सुनिश्चित करना।
- लिंगानुपात अंतर को कम करना।
- लगभग 5 किमी. के दायरे में माध्यमिक विद्यालय का निर्माण तथा लगभग 7 से 10 किमी के दायरे में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण ~~सुनिश्चित~~ के साथ सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था तथा परिस्थितियों के अनुसार आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की तरजीह दी जा सकती है।
- सुदूरवर्ती इलाकों में शिक्षकों के लहराव को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय परिसर में ही आवासीय सुविधा का निर्माण करना।
- माध्यमिक शिक्षा से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण या आयोजन करना।
- शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना तथा विद्यालयों में खेल सुविधाओं की व्यवस्था करना।

RMSA में केन्द्र एवं राज्य सरकार की विज्ञान व्यवस्था

- प्रारम्भ में केन्द्र व राज्य सरकार की 75:25 की साझेदारी थी।
- पूर्वोत्तर राज्यों में यह साझेदारी 90:10 की थी।
- वर्तमान में 12वीं योजना के अनुसार यह सम्पूर्ण भारत में 50:50 की साझेदारी है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की आवश्यकता

- विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी की शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने हेतु।
- सामाजिक ~~समस्या~~, आर्थिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव की समाप्ति।
- माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु।
- अतिरिक्त कक्षा - कक्षाओं के निर्माण हेतु।
- कंप्यूटर कक्षा - कक्षा के निर्माण हेतु।
- पुस्तकालयों की स्थापना।
- विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण।
- शिक्षकों की सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था।

- विद्यालयों में पीने योग्य पानी की सुविधा ।
- विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण ।
- सांस्कृतिक कक्षा - कक्षा का निर्माण ।
- शिल्पकला एवं कला कक्षा का निर्माण ।
- विद्यालयों की मरम्मत सम्बन्धी सुविधा ।
- माध्यमिक शिक्षा की सावर्भौतिक व्यवस्था ।